

वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025 पर सर्वोच्च न्यायालय का अंतरिम आदेश

[स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस](#)

चर्चा में क्यों?

भारत के सर्वोच्च न्यायालय (SC) ने वक्फ (संशोधन) अधिनियम 2025 के कुछ प्रावधानों पर रोक लगा दी है, यह चिंता जताते हुए कयिह अनुच्छेद 26 का उल्लंघन करता है, प्रशासनिक शक्तियों और वक्फ बोर्डों पर गैर-मुस्लिम प्रतिनिधित्व के माध्यम से समुदाय की स्वायत्तता को कमजोर करता है तथा मौजूदा वक्फ संपत्तियों एवं परोपकार पर प्रभाव डाल सकता है।

वक्फ अधिनियम, 1995 क्या है?

- **वक्फ अधिनियम, 1995**, भारत में एक केंद्रीय अधिनियम है जो वक्फ संपत्तियों, धार्मिक या चैरिटेबल/परोपकारी उद्देश्यों के लिये मुस्लिम कानून के तहत संपत्ति के दान के बेहतर प्रशासन, प्रबंधन तथा संरक्षण के लिये प्रावधान करता है।
 - यह इन संपत्तियों की नगरानी के लिये राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर वक्फ बोर्डों की स्थापना करता है, ताकयिह सुनिश्चित किया जा सके कयिे संपत्तियाँ अपने नरिधारित उद्देश्यों के लिये उपयोग की जाएँ तथा पारदर्शी एवं कानूनी तरीके से प्रबंधित की जाएँ।
- **वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025 UMEED (एकीकृत वक्फ प्रबंधन, अधिकारिता, दक्षता और विकास अधिनियम)**, वक्फ अधिनियम, 1995 में संशोधन करता है।
 - **वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025 के मुख्य प्रावधान:**
 - **ट्रस्ट का बहिष्कार:** यदि मुस्लिम द्वारा बनाए गए ट्रस्ट अन्य धर्मार्थ कानूनों के अंतर्गत शासित हैं तो वे कानूनी रूप से वक्फ से अलग माने जाएंगे।
 - **उत्तराधिकार अधिकारों का संरक्षण:** महिलाओं और बच्चों को उनकी वैध वरिष्ठ प्राप्त करनी चाहिये, इससे पहले कसंपत्ति वक्फ बन जाएँ।
 - **जनजातीय भूमिका संरक्षण:** यह [संवधान की पाँचवीं और छठी अनुसूचियों](#) के तहत जनजातीय समुदायों की भूमि पर वक्फ की स्थापना पर प्रतिबंध लगाता है।
 - **अपील तंत्र:** उच्च न्यायालय वक्फ न्यायाधिकरण के नरिणयों के खिलाफ अपील सुन सकता है।
 - **वित्तीय सुधार:** वक्फ बोर्डों में अनविर्य योगदान 7% से घटाकर 5% कर दिया गया है।
 - **आय लेखा परीक्षा:** 1 लाख रुपए से अधिक वार्षिक आय वाली वक्फ संस्थाएँ सरकार द्वारा अनविर्य लेखा परीक्षा के अधीन हैं।

वक्फ बोर्ड

- वक्फ बोर्ड एक वधिक इकाई है जो संपत्ति अर्जति कर सकती है, उसे धारण कर सकती है, हस्तांतरित कर सकती है और उस पर मुकदमा चलाया जा सकता है।
- यह **वक्फ संपत्तियों** (धार्मिक या परोपकारी उद्देश्यों के लिये समर्पित संपत्ति) का प्रबंधन करता है, खोई हुई संपत्तियों की वसूली करता है और हस्तांतरणों (बिक्री, उपहार, बंधक, वनिमि, पट्टा) को कम से कम दो-तहिई बोर्ड अनुमोदन के साथ मंजूरी देता है।
- **केंद्रीय वक्फ परिषद (CWC)** अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय के तहत एक सांवधिक निकाय है, जो राज्य वक्फ बोर्डों की देख-देख और सलाह देता है।

वक्फ संशोधन अधिनियम, 2025 के प्रमुख वविदास्पद प्रावधान क्या हैं और इस पर सर्वोच्च न्यायालय का रुख क्या है?

- सर्वोच्च न्यायालय द्वारा समर्थित प्रावधान:

- परसीमा अधिनियम की प्रयोज्यता: **वक्फ अधिनियम, 1995** ने परसीमा अधिनियम, 1963 के अनुप्रयोग को विशेष रूप से बाहर रखा था, जो वक्फ को बना क़िसी समय सीमा के अपनी संपत्तियों पर अतिक्रमण के वरिद्ध कार्रवाई करने की अनुमति देता था।
 - वक्फ संशोधन अधिनियम, 2025** : इस छूट को समाप्त कर देता है और कानूनी दावों को नरिदषिट अवध के भीतर दायर करना अनविर्य बनाता है।
 - न्यायालय ने इस प्रावधान को बरकरार रखा तथा कहा कयिह पहले के भेदभाव को ठीक करता है।
- "उपयोग द्वारा वक्फ" का **उन्मूलन**: पहले, यदाभूमलिंभे समय तक मुसलमि धार्मकि/धार्मकि उद्देश्यों के लयि उपयोग में लाई जाती थी तो उसे **बनि पंजीकरण** के भी वक्फ माना जा सकता था। वर्ष 2025 संशोधन अधिनियम ने **दुरुपयोग का हवाला देते हुए "उपयोग द्वारा वक्फ"** की अवधारणा को समाप्त कर दिया।
 - सर्वोच्च न्यायालय ने इस बात को बरकरार रखा क इसका दुरुपयोग सरकारी भूमि पर अतिक्रमण के लयि कयिा गया है तथा इस पर रोक लगाने का प्रथम दृष्टया कोई कारण नहीं पाया गया।
- सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रोकें गए प्रावधान:**
 - पाँच साल का नयिम मुसलमिों के लयि:** संशोधति अधिनियम के अनुसार, कोई **वक्फ** केवल उस वयक्ति द्वारा स्थापति कयिा जा सकता है, जसिने कम-से-कम पाँच वर्षों तक इस्लाम का अभ्यास कयिा हो।
 - सर्वोच्च न्यायालय ने इस प्रावधान को स्थगति कर दिया है, कयोंकि सरकार द्वारा स्पष्ट नयिम बनाए जाने तक धार्मकि अभ्यास की जाँच का कोई तंत्र नहीं है।
 - ज़िला कलेक्टरों के अधिकार (धारा 3C):** संशोधति अधिनियम के अनुसार, ज़िला कलेक्टर अपनी जाँच के दौरान कसिी **वक्फ संपत्ति** को सरकारी संपत्ति घोषति कर सकते हैं (जाँच की अवध के दौरान उस संपत्ति को वक्फ संपत्ति के रूप में नहीं माना जाएगा)।
 - सर्वोच्च न्यायालय ने इस प्रावधान को **अस्थायी रूप से स्थगति** कर दिया है, इसे **मनमाना और शक्तियों का पृथक्करण** का उल्लंघन बताते हुए, कयोंकि संपत्ति विवादों का नरिणय केवल **ट्रिब्यूनल (अधिकरणों)** या **न्यायालयों** द्वारा कयिा जाना चाहयि।
 - सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार, जाँच की अवध में **वक्फ संपत्तियों का दर्जा यथावत रहेगा**, उन पर कब्ज़ा नहीं हटाया जा सकेगा और वक्फ ट्रिब्यूनल के अंतिम नरिणय तक कसिी नए **तृतीय पक्ष को अधिकार** नहीं दिया जाएगा।
 - वक्फ बोर्डों में गैर-मुसलमि प्रतिनिधित्व:** इस अधिनियम ने **वक्फ बोर्डों और केंद्रीय वक्फ परिषद** में बड़ी संख्या में गैर-मुसलमानों को शामिल करने की अनुमति दी है।
 - सर्वोच्च न्यायालय द्वारा गैर-मुसलमि प्रतिनिधित्व पर रोक:
 - केंद्रीय वक्फ परिषद (22 सदस्य) में 4 से अधिक गैर-मुसलमान नहीं होंगे।
 - राज्य वक्फ बोर्ड (11 सदस्य) में 3 से अधिक गैर-मुसलमान नहीं होंगे।

भारत में धार्मकि स्वतंत्रता के संबंध में प्रमुख न्यायकि नरिणय:

- बजिो इमैनुएल बनाम केरल राज्य, 1987:** सर्वोच्च न्यायालय ने कहा क अगर राष्ट्रगान उनकी धार्मकि मान्यताओं का उल्लंघन करता है तो छात्रों को उसे गाने के लयि बाध्य नहीं कयिा जा सकता।
 - इस नरिणय ने स्थापति कयिा क वयक्ति को उन गतिविधियों में भाग लेने से इंकार करने का अधिकार है जो उसकी धार्मकि मान्यताओं के वरिद्ध हों, बशर्ते क उससे सार्वजनकि व्यवस्था भंग न हो।
- शायरा बानो बनाम भारत संघ, 2017:** सर्वोच्च न्यायालय ने एक साथ **तीन तलाक (तलाक-ए-बदिदत)** को असंवैधानकि बताते हुए इसे रद्द कर दिया, कयोंकि यह अनुच्छेद 14 (समानता का अधिकार) और लैंगकि न्याय सिद्धांतों का उल्लंघन करता है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा क यह अनुच्छेद 25 के तहत एक आवश्यक धार्मकि प्रथा नहीं है।
- डॉ. महेश वजिय बेडेकर बनाम महाराष्ट्र, 2016:** सर्वोच्च न्यायालय ने माना क लाउडस्पीकर का उपयोग एक आवश्यक धार्मकि प्रथा नहीं है और इसे अनुच्छेद 25 (धार्मकि स्वतंत्रता) या अनुच्छेद 19(1)(a) (भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता) के तहत मौलकि अधिकार के रूप में दावा नहीं कयिा जा सकता।

नषिकरष:

वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025 सुधारों का लक्ष्य रखता है, लेकिन यह **स्वायत्तता और अधिकारों को लेकर गंभीर चिंताएँ भी उत्पन्न** करता है। सर्वोच्च न्यायालय का अंतरिम आदेश **संवैधानकि सुरक्षा** उपायों के साथ सुधार प्रक्रिया को सावधानीपूर्वक संतुलति करने का प्रयास करता है। आगे की राह **पारदर्शति और जवाबदेही को बढ़ावा देने पर केंद्रति** होनी चाहयि, साथ ही समुदायों के बीच **धार्मकि स्वतंत्रता और वशिवास की भावना** को भी बनाए रखना चाहयि।

और पढ़ें: **वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025**

?????? ???? ????:

प्रश्न: वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025 का उद्देश्य वक्फ प्रशासन का आधुनिकीकरण कसि प्रकार करना है तथा इसके समक्ष क्या चुनौतियाँ हैं?

संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न (PYQs)

2018:

प्रश्न: भारतीय धर्मनरिपेक्षता की अवधारणा पश्चिमी धर्मनरिपेक्षता मॉडल से कसि प्रकार भन्नि है? वविचना कीजयि । (2018)

PDF Refernece URL: <https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/supreme-courts-interim-order-on-the-waqf-amendment-act-2025>

